

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग ॥—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935

No. 147]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

### वित्त मंत्रालय

# (राजस्व विभाग)

## अधिसचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2014

### सं. 13/2014 - केन्द्रीय उत्पाद शल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 201(अ). — केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12गगग तथा सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 12गगग तथा सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 12ककक के अनुसरण में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 13 मार्च, 2012 को सा.का.नि. सं. 142 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित दिनांक 13 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 6/2012- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), को निरस्त किए जाने से पूर्व की गई मदों अथवा विलोपित की जाने वाली मदों को छोड़कर एतदद्वारा निरस्त करती है।

[फा. सं. 267/13/2013- सीएक्स-8]

REGD. NO. D. L.-33004/99

पंकज जैन, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2014

No. 13/2014 - Central Excise (N.T.)

**G.S.R. 201(E).**—In pursuance of rule 12CCC of the Central Excise Rules, 2002, and rule 12AAA of the CENVAT Credit Rules, 2004, the Central Board of Excise and Customs hereby rescinds the notification No. 6/2012-Central Excise (N.T.) dated the 13th March, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 142(E) dated the 13th March, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 267/13/2013-CX.8] PANKAJ JAIN, Under Secy.

1303 GI/2014 (1)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2014

## सं. 14/2014 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 202(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 में और आगे संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 है।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागृ होंगे।
- 2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 गगग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"12 गगग- कितपय मामलों में प्रतिबंध लगाने का अधिकार- इन नियमों में किसी भी बात के होने के बावजूद केन्द्र सरकार का, कर अपवंचन, अपराधों के स्वरूप अथवा प्रकार अथवा अन्य संगत कारकों के आलोक में यदि यह मत हो कि कर अपवंचन को रोकने अथवा उत्पाद शुल्क के भुगतान में चूक को रोकने के लिए, लोकहित में निर्माता, प्रथम चरण और द्वितीय चरण डीलर अथवा किसी निर्यातक पर प्रतिबंध लगाने सहित कितपय उपायों का प्रावधान करना लोकहित में आवश्यक है तो यह किसी डीलर के मामले में पंजीकरण को रद्द करने, वापस लिए जाने वाली सुविधाओं के प्रकार और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए जाने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने सहित लगाये जाने वाले प्रतिबंधों के स्वरूप, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन से एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.िन. सं. 140(अ), के अंतर्गत दिनांक 12 मार्च, 2012 को प्रकाशित दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना 05/2012- सीई (गै.टे.) के तहत् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार शुरू किया गया प्रत्येक प्रस्ताव, जो लंबित है, इस नियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार शुरू किया गया प्रस्ताव माना जाएगा तथा उस पर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।"

[फा. सं. 267/13/2013-सीएक्स-8]

पंकज जैन. अवर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 143(अ), के अंतर्गत दिनांक 1 मार्च, 2002 को दिनांक 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना 04/2002- सीई (गै.टे.), के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 134(अ), दिनांक 1 मार्च, 2014 के अंतर्गत दिनांक 28 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. 08/2014 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st March, 2014

### No. 14/2014 - Central Excise (N.T.)

**G.S.R. 202(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Central Excise (Second Amendment) Rules, 2014.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. For rule 12CCC of the Central Excise Rules, 2002, the following shall be substituted, namely:—
  - "12CCC. Power to impose restrictions in certain types of cases.— Notwithstanding anything contained in these rules, where the Central Government, having regard to the extent of evasion of duty, nature and type of offences or such other factors as may be relevant, is of the opinion that in order to prevent evasion of, or default in payment of duty of excise, it is necessary in the public interest to provide for certain measures including

restrictions on a manufacturer, first stage and second stage dealer or an exporter may, by notification in the Official Gazette, specify the nature of restrictions including suspension of registration in case of a dealer, types of facilities to be withdrawn and procedure for issue of such order by the Chief Commissioner of Central Excise.

**Explanation.**—For the purposes of this rule, it is hereby clarified that every proposal initiated in terms of the procedure specified under notification no. 05/2012-CE (N.T.) dated the 12<sup>th</sup> March, 2012 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 140(E), dated the 12<sup>th</sup> March, 2012, which is pending, shall be treated as initiated in terms of the procedure specified under this rule and shall be decided accordingly."

[F. No. 267/13/2013-CX.8]

PANKAJ JAIN, Under Secy.

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number 04/2002-CE(NT), dated the 1st March, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 143(E), dated the 1st March 2002 and were last amended vide notification number 08/2014-Central Excise (NT) dated the 28th February, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 134 (E), dated the 1st March, 2014.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2014

### सं. 15/2014 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 203(अ) .— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में और आगे संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का नाम सेनवेट क्रेडिट (पांचवा संशोधन) नियमावली, 2014 है।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 12 ककक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"12 ककक - कितपय मामलों में प्रतिबंध लगाने का अधिकार- इन नियमों में किसी भी बात के होने के बावजूद केन्द्र सरकार का, सेनवेट क्रेडिट के दुरूपयोग, ऐसे दुरूपयोग के स्वरूप अथवा प्रकार अथवा अन्य संगत कारकों के आलोक में यदि यह मत हो कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार सेनेवेट क्रेडिट प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, लोकहित में निर्माता, प्रथम चरण और द्वितीय चरण डीलर अथवा किसी निर्यातक पर प्रतिबंध लगाने सहित कितपय उपायों का प्रावधान करना लोकहित में आवश्यक है तो यह सेनवेट क्रेडिट की उपियोगिता और किसी डीलर के मामले में पंजीकरण को रद्द करने, वापस लिए जाने वाली सुविधाओं के प्रकार और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए जाने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने सहित लगाये जाने वाले प्रतिबंधों को, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन से एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 140(अ), के अंतर्गत दिनांक 12 मार्च, 2012 को प्रकाशित दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना 05/2012- सीई (गै.टे.) के तहत् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार शुरू किया गया प्रत्येक प्रस्ताव, जो लंबित है, इस नियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार शुरू किया गया प्रस्ताव माना जाएगा तथा उस पर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।"

[फा. सं. 267/13/2013-सीएक्स-8]

पंकज जैन. अवर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 600 (अ), के अंतर्गत दिनांक 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना 23/2004- सीई (गै.टे.), के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 135(अ), दिनांक 1 मार्च, 2014 के अंतर्गत दिनांक 28 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. 09/2014- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st March, 2014

### No. 15/2014 - Central Excise (N.T.)

**G.S.R. 203(E).**— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Fifth Amendment) Rules, 2014.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. (1) For rule 12AAA of the CENVAT Credit Rules, 2004, the following shall be substituted, namely:—

"12AAA. Power to impose restrictions in certain types of cases.— Notwithstanding anything contained in these rules, where the Central Government, having regard to the extent of misuse of CENVAT credit, nature and type of such misuse and such other factors as may be relevant, is of the opinion that in order to prevent the misuse of the provisions of CENVAT credit as specified in these rules, it is necessary in the public interest to provide for certain measures including restrictions on a manufacturer, first stage and second stage dealer or an exporter, may by notification in the Official Gazette, specify the nature of restrictions including restrictions on utilization of CENVAT credit and suspension of registration in case of a dealer and type of facilities to be withdrawn and procedure for issue of such order by the Chief Commissioner of Central Excise.

Explanation.- For the purposes of this rule, it is hereby clarified that every proposal initiated in terms of the procedure specified under notification no. 05/2012-CE (N.T.) dated the 12th March, 2012 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 140(E), dated the 12th March, 2012, which is pending, shall be treated as initiated in terms of the procedure specified under this rule and shall be decided accordingly."

[F. No. 267/13/2013-CX.8]

PANKAJ JAIN, Under Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004, vide Notification No. 23/2004 – Central Excise (N.T.) dated the 10th September, 2004, vide number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended vide Notification No. 09/2014-Central Excise (N.T.) dated the 28th February, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 135 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2014.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2014

## सं. 16/2014 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 204(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12गगग और सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 12ककक के अनुसरण में तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 05/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 12 मार्च, 2012, जिसे सा.का.िन. 140(अ), दिनांक 12 मार्च, 2012 के तहत, सिवाय जहां तक ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्यों का संबंध है, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा, घोषित करती है कि जहां कहीं भी कोई विनिर्माता, प्रथम चरण या दूसरे चरण का डीलर या कोई निर्यातकर्ता, जिसमें व्यापारी निर्यातकर्ता भी शामिल है, प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है कि वह निम्न में से किसी भी कार्य में शामिल है:—

- (क) बीजक के दायरे में आये बिना और बिना शुल्क के भुगतान के माल को हटाना;
- (ख) शुल्क के भुगतान के प्रयोजनार्थ सही मूल्य की घोषणा किये बिना माल को हटा ले जाना जहां कि बिक्री मूल्य का एक हिस्सा, बीजक मूल्य से जितना अधिक है, वह प्राप्त कर लेता है या उसकी ओर से प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन उसे बही-खाते में दर्ज नहीं किया जाता है;
- (ग) ऐसे दस्तावेज में विनिर्दिष्ट माल की रसीद के बिना सेनवेट क्रेडिट का लेना जिसके आधार पर उक्त क्रेडिट ली गई है;

- (घ) ऐसे बीजक या अन्य दस्तावेज पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना जिसके बारे में किसी भी व्यक्ति के लिए यह जानने का कारण है कि यह सही नही है;
- (ङ) उक्त बीजक में विनिर्दिष्ट माल की डिलीवरी के बिना उत्पाद शुल्क के बीजक का जारी करना;
- (च) ऐसे बीजक या अन्य दस्तावेज पर भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क के आधार पर धन वापसी या छूट का दावा करना जिसके बारे में किसी व्यक्तिविशेष के पास विश्वसनीय कारण है कि वह सही नहीं है;
- (छ) ऐसे आदानों को हटाना जिस पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया है, ऐसा सेनवेट क्रेडिट रुल्स, 2004 के नियम 3 के उपनियम (5) के अनुसार ऐसे आदानों पर प्राप्त किये गये क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान किये बिना करना।

तो मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इस अधिसूचना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट, सुविधाओं को वापस ले सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है।

- 2. वापस ली जाने वाली सुविधायें तथा लगाये जाने वाले प्रतिबंध:- (1) जहां कि कोई विनिर्माता प्रथम दृष्टया, पैरा-। में विनिर्दिष्ट अपराधों को जानबूझ कर करने में संलग्न पाया जाता है तो मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उतपाद शुल्क इन सुविधाओं पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगा सकता है, यथा:-
  - i. निर्धारिती से शुल्क का भुगतान मासिक किये जाने की सुविधा को वापस लिया जा सकता है और तब उसके लिये यह जरूरी हो जायेगा कि वह प्रत्येक खेप के लिये उत्पादन शुल्क का भुगतान माल को हटाते समय करे।
  - सेनवेट क्रेडिट के उपयोग के द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान करने से रोका जा सकता है और तब निर्धारिती के लिये
     यह जरूरी हो जायेगा कि वह सेनवेट क्रेडिट के उपयोग के बिना ही उत्पाद शुल्क का भुगतान करे।
  - iii. निर्धारिती के लिये यह जरूरी किया जा सकता है कि वह उन प्रधान आदानों की भी प्राप्ति, निपटान, उपभोग और बीजक का हिसाब-किताब रखे जिसपर सेनवेट क्रेडिट नहीं प्राप्त किया गया है।
  - iv. निर्धारिती के लिये यह जरूरी किया जा सकता है कि वह कारखाने में प्रधान आदान जिसपर चाहे सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं, की प्राप्ति के बारे में अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, को इस आदेश में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, संसूचित करें और उक्त आदान को इस आदेश में विनिर्दिष्ट अविध तक सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाए।

बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किसी या एक से अधिक प्रकार के अपराधों को जानबूझ कर करने में तदन्तर भी संलग्न पाया जाता है, उसके कारखाने से माल की प्रत्येक निकासी के लिए आदेश दिया जा सकता है कि यह बीजक के अंतर्गत किया जाए और जिसपर निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उक्त माल को कारखाने या भंडागार से हटाये जाने के पहले प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी होगा।

स्पष्टीकरण- इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिये, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

- i. ऐसा कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है, सेनवेट क्रेडिट लेता रह सकता है, हालांकि वह उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान शुल्क के भुगतान के लिए उक्त क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा।
- ii. 'प्रधान आदान' से अभिप्राय ऐसे किसी भी आदान से है जिसका प्रयोग अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में होता है जहां ऐसे आदानों की लागत किसी दिये गये अंतिम उत्पाद की इकाई मात्रा के विनिर्माण में प्रयुक्त कुल कच्चे माल की लागत के 10 प्रतिशत से कम नहीं है।
- iii. यदि निर्धारिती पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को पहली बार करता है तो प्रतिबंधों को लगाए जाने की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती।
- iv. यदि निर्धारिती पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को तदंतर करता है, तो प्रतिबंधों को लगाए जाने की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (2) जहां पहले चरण अथवा दूसरे चरण का डीलर पैरा 1 की धारा (घ) अथवा (ड.) में विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराध को जानबूझकर करने में शामिल पाया जाता है, तो मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नियमावली, 2002 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबन का आदेश कर सकता है।

- (3) निलम्बन की अवधि के दौरान उक्त डीलर कोई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बीजक जारी नहीं करेगा;

  किन्तु, वह अपना व्यापार जारी रख सकता है और बीजक में उत्पाद शुल्क प्रदर्शित किए बिना बिक्री बीजक जारी कर सकता है और ऐसी बीजक के अंतर्गत वस्तुओं के प्राप्तकर्ता को कोई सेनवेट क्रेडिट देय नहीं होगा।
- (4) जहां कोई निर्यातक व्यापारी जानबूझकर पैरा 1 के उपवाक्य (च) में विनिर्दिष्ट प्रकार का अपराध करने का दोषी पाया जाता है, वहां मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात समनुदेशन हेतु स्वत: सील करने की सुविधा वापस लेने का आदेश कर सकता है, जिसके बाद निर्यात प्रेषण वहां के क्षेत्राधिकार के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा जांच तथा सील किया जाएगा:
- (5) यदि कोई विनिर्माता, प्रथम चरण या दूसरे का डीलर या कोई निर्यातकर्ता पैरा (1) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करता है तो मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उनको प्राप्त अन्य सुविधाओं को भी वापस ले सकता है।
- 3. आर्थिक सीमा:- इस अधिसूचना से संबंधित प्रावधान उन स्थितियों में ही लागू होंगे, जहां पैरा 1 में विनिर्दिष्ट अपराधों के संदर्भ में आरोपित शुल्क या सेनवेट क्रेडिट 10 लाख रुपये से अधिक है ।
- 4. प्रक्रिया:- (1) आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा अपर महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना, जैसा लागू हो दस्तावेज तथा अन्य प्रमाणों के जांच के बाद और अपने आपको संतुष्ट करने के बाद कि उस व्यक्ति ने जान बूझकर पैरा 1 में वर्णित अपराध किया है, एक प्रस्ताव, मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को वापस ली जाने वाली सुविधाओं तथा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की सूची उनकी समय सीमाओं के साथ जिस दौरान ये वापस लिये जाएंगे या प्रतिबंधित किए जायेंगे जहां तक संभव हो, मामले में, पता चलने के तीस दिनों के भीतर भेजेगा।
  - (2) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उक्त प्रस्ताव की जांच करेगा तथा प्रस्ताव के साथ प्राप्त दस्तावेज तथा प्रमाणों से अपने आपको संतुष्ट करने के बाद यदि पाता है कि वे प्रथम दृष्ट्या यह उचित विश्वास करने योग्य है, कि उस व्यक्ति ने जान बूझकर पैरा 1 में वर्णित अपराध किया है, वापस ली जाने वाली सुविधाओं और लगाए जाने वाले प्रतिबंधों संबंधी उन समय सीमाओं के साथ जिसमें ये सुविधाएं नहीं दी जाएगी या जिस दौरान प्रतिबंध लागू रहेंगे को विनिर्दिष्ट करते हुए एक आदेश पारित करे:

बशर्ते कि मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदेश किए जाने से पूर्व, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की जा रही है, को अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर देगा और उस पर विचार करने के बाद ही आदेश पारित करेगा।

5. अधिसूचना सं. 05/2012 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 12 मार्च, 2012 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आसूचना के समक्ष जो प्रस्ताव लिम्बित हैं, इस अधिसूचना की प्रभावी तिथि से मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को अंतरित होगी, जो पैराग्राफ 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में इसका निर्णय करेगा और मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समक्ष लिम्बित प्रस्तावों पर भी तद्नुसार निर्णय किया जाएगा।

[फा. सं. 267/13/2013-सी एक्स-8]

पंकज जैन, अवर सचिव

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st March, 2014

No. 16/2014 - Central Excise (N.T.)

G.S.R.204 (E).—In pursuance of rule 12CCC of the Central Excise Rules, 2002, and rule 12AAA of the CENVAT Credit Rules, 2004 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 05/2012-Central Excise (N.T.), dated the 12th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 140(E), dated the 12th March, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby

declares that where a manufacturer, first stage or second stage dealer, or an exporter including a merchant exporter is prima facie found to be knowingly involved in any of the following:-

- (a) removal of goods without the cover of an invoice and without payment of duty;
- (b) removal of goods without declaring the correct value for payment of duty, where a portion of sale price, in excess of invoice price, is received by him or on his behalf but not accounted for in the books of account;
- (c) taking of CENVAT Credit without the receipt of goods specified in the document based on which the said credit has been taken;
- (d) taking of CENVAT Credit on invoices or other documents which a person has reasons to believe as not genuine;
- (e) issuing duty of excise invoice without delivery of goods specified in the said invoice;
- (f) claiming of refund or rebate based on the duty of excise paid invoice or other documents which a person has reason to believe as not genuine;
- (g) removal of inputs as such on which Cenvat credit has been taken, without paying an amount equal to credit availed on such inputs in terms of sub-rule (5) of rule 3 of the Cenvat Credit Rules, 2004,

the Chief Commissioner of Central Excise may order for withdrawal of facilities or impose the restrictions as specified in para 2 of this notification.

- **2. Facilities to be withdrawn and imposition of restrictions.-** (1) Where a manufacturer is prima facie found to be knowingly involved in committing the offences specified in para 1, the Chief Commissioner of Central Excise may impose following restrictions on the facilities, namely:-
  - (i) the monthly payment of duty of excise may be withdrawn and the assessee shall be required to pay duty of excise for each consignment at the time of removal of goods;
  - (ii) payment of duty of excise by utilisation of CENVAT credit may be restricted and the assessee shall be required to pay duty of excise without utilising the CENVAT credit;
  - (iii) the assessee may be required to maintain records of receipt, disposal, consumption and inventory of the principal inputs on which CENVAT credit has not been taken;
  - (iv) the assessee may be required to intimate the Superintendent of Central Excise regarding receipt of principal inputs in the factory on which CENVAT credit has or has not been taken, within a period specified in the order and the said inputs shall be made available for verification upto the period specified in the order:

Provided that where a person is found to be knowingly involved in committing any one or more type of offences as specified in para 1 subsequently, every removal of goods from his factory may be ordered to be under an invoice which shall be countersigned by the Inspector of Central Excise or the Superintendent of Central Excise before the said goods are removed from the factory or warehouse.

**Explanation.-** For the purposes of this paragraph, it is clarified that-

- (i) a person against whom the order under sub-para (2) of para 4 has been passed may continue to take CENVAT credit, however, he would not be able to utilize the credit for payment of duty during the period specified in the said order.
- (ii) "principal inputs" means any input which is used in the manufacture of final products where the cost of such input constitutes not less than 10% of the total cost of raw materials for the manufacture of unit quantity of a given final product.
- (iii) if the assessee commits any offence specified in para 1 for the first time, the period of imposition of restrictions may not be more than 6 months.
- (iv) if the assessee commits any offence specified in para 1 subsequently, the period of imposition of restrictions shall not be more than 1 year.
- (2) Where a first stage or second stage dealer is found to be knowingly involved in committing the type of offence specified at clauses (d) or (e) of para 1, the Chief Commissioner of Central Excise may order suspension of the registration granted under rule 9 of the Central Excise Rules, 2002 for a specified period.
- (3) During the period of suspension, the said dealer shall not issue any Central Excise Invoice:

- Provided that he may continue his business and issue sales invoices without showing duty of excise in the invoice and no CENVAT credit shall be admissible to the recipient of goods under such invoice.
- (4) Where a merchant exporter is found to be knowingly involved in committing the type of offence specified in clause (f) of para 1, the Chief Commissioner of Central Excise may order withdrawal of the self sealing facility for export consignment and each export consignment shall be examined and sealed by the jurisdictional Central Excise Officer:
- (5) If a manufacturer, first stage dealer or second stage dealer or an exporter does anything specified in clause (f) of para 1, the Chief Commissioner of Central Excise may order withdrawal of the other facility available to them.
- **3. Monetary limit.-** The provisions of this notification shall be applicable only in a case where the duty of excise or CENVAT Credit alleged to be involved in anything specified in para 1 exceeds rupees ten lakhs.
- **4. Procedure.-** (1) The Commissioner of Central Excise or Additional Director General of Central Excise Intelligence, as the case may be, after examination of records and other evidence, and after satisfying himself that the person has knowingly committed the offence as specified in para 1, may forward a proposal to the Chief Commissioner of Central Excise, to withdraw the facilities and impose restriction during or for such period, within 30 days of the detection of the case, as far as possible.
- (2) The Chief Commissioner of Central Excise shall examine the said proposal and after satisfying himself that the records and evidence relied upon in the said proposal are sufficient to form a reasonable belief that the person has knowingly done or contravened anything specified in para 1, may issue an order specifying the type of facilities to be withdrawn or type of restrictions to be imposed, along with the period for which the said facilities will not be available or the period for which the restrictions shall be operative:

*Provided* that the Chief Commissioner of Central Excise, before issuing the order, shall give an opportunity of being heard to the person against whom the proceedings have been initiated and shall take into account any representation made by such person before he issues the order.

5. Proposals which are pending before the officer authorized by the Central Board of Excise and Customs or the Director General of Central Excise Intelligence in terms of notification no. 05/2012-Central Excise (N.T.), dated the 12<sup>th</sup> March, 2012, on the date of coming into force of this notification, shall be transferred to the Chief Commissioner of Central Excise, who shall decide the same in accordance with the procedure specified in paragraph 4 and the proposals pending before the Chief Commissioner of Central Excise shall also be decided accordingly.

[F. No. 267/13/2013-CX.8]

PANKAJ JAIN, Under Secy.